• फायदा...

होटल्स में मिल रहा 40 फीसदी डिस्काउंट

शिमला : मानसून सीजन के चलते हिमाचल में पर्यटकों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में एचपीटीडीसी के होटल में पर्यटकों के लिए 20 से 40 प्रतिशत डिस्काउंट मिल रहा है. ये डिस्काउंट हिमाचल पर्यटन विकास निगम के प्रदेश भर में स्थित 41 होटलो में पर्यटकों को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने मंगलवार को मानसून सीजन के दौरान 15 जुलाई से 13 सितंबर तक डिस्काउंट की घोषणा की है।

एचपीटीडीसी के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि मानसून सीजन के दौरान पर्यटकों की संख्या कम हो जाती है। सीजन को ध्यन में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। एचपीटीडीसी होटलों के मार्केटिंग स्टेटर्जी के लिए के लिए सभी प्रयास करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं कि अधिकतम पर्यटक इसका लाभ उठाएं। हालांकि, होटल स्पीति (काजा), होटल किन्नर कैलाश (कल्पा), सन एंड स्नो कॉटेज (कल्पा), होटल चंद्रभागा (केलांग), होटल शिवालिक परवाणू), होटल हमीर (हमीरपुर), लेक व्यू (बिलासपुर), होटल बाघल (दारलाघाट), होटल नूरपुर

(नूरपुर), होटल बुशहर रीजेंसी (रामपुर), सुकेत (सुंदरनगर) और होटल विलीज पार्क (शिमला) में कोई छूट नहीं दी जाएगी.

मिंजर मेले के दौरान 28 जुलाई से 4 अगस्त तक होटल इरावती, चंबा में होटल चंपक और भरमौर में होटल गौरीकुंड में कोई छूट लागू नहीं होगी। इसके अलावा, 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मणिमहेश यात्रा के दौरान होटल गौरीकुंड में छूट उपलब्ध नहीं होगी। पिछले साल मानसून आपदा ने हिमाचल प्रदेश में कहर बरपाया था और मानसून सीजन के दौरान लगभग 550 लोग मारे गए थे।

द गोल्फ ग्लेड नालदेहरा, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल एपल ब्लॉसम फागू, न्यू रोज कॉमन कसौली, मणिमहेश डलहौजी, द पैलेस चायल, होटल हाटू नारकंडा और होटल धौलाधार धर्मशाला में 40 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा।

• हाईटेक...

एचपीटीडीसी हुआ पूरी तरह से पेपरलेस

शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पेपरलेस होने के बाद सरकार के सभी विभागों निगम और बोर्ड में इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा रहा है। एचपीटीडीसी अब इस प्रक्रिया के तहत हाईटेक हो गया है. अब पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) पेपरलेस हो गया है।

निगम के सभी होटल, रेस्टोरेंट और कैफे का रिकॉर्ड डिजिटल हो गया है। इससे एचपीटीडीसी को घाटे से उबरने में मदद मिलेगी। वहीं, निगम के सारे रिकॉर्ड अब फाइलों की जगह ऑनलाइन मिलेंगे। इसके अलावा होटलों के हर कामकाज की जानकारी का रिकॉर्ड ई-ऑफिस पर ऑनलाइन मिलेगा।

अधिकारी कार्यालय, घर एवं प्रदेश के बाहर कहीं से भी फाइलों को डिजिटल साइन के माध्यम से निपटा सकेंगे। एचपीटीडीसी सरकार का पहला उपक्रम है, जिसे पूरी तरह से ई-ऑफिस की सुविधा से जोड़ा गया है. इसका मकसद निगम के कामकाज को पूरी तरह पेपरलेस बनाना है।

हिमाचल पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने कहा पेपरलेस की प्रक्रिया इस वर्ष के जनवरी माह से शुरू हो गई थी। अब एचपीटीडीसी पूरी तरह पेपरलेस हो गया है पहले अगर कर्मचारी छुट्टी पर चले जाएं तो काम प्रभावित होता था, परंतु पेपरलेस होने के बाद काम प्रभावित नहीं होता।

इस प्रक्रिया से अतिरिक्त खर्चा भी कम हो गया है। पेपरलेस प्रक्रिया के लिये कर्मचारियों को हिपा में प्रशिक्षण दिया गया। सभी कर्मचारियों को पेपरलेस प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया गया अगर कर्मचारी या अधिकारी फील्ड पर भी हों फिर भी कार्य को मोबाइल के माध्यम से उसी समय ई-प्रणाली के तहत निपटा सकते हैं। अब प्रदेशभर की 65 होटल इकाइयों को ई-ऑफिस की सुविधा से लेस किया गया है। पहले कार्यालय में एक से दूसरी जगह जाकर फाइलों को मंजूरी मिलती थी। इसमें काफी समय लगता था और टेबलों पर फाइलों का ढेर लग जाता था। अफसर घर बैठे या टूअर पर भी फाइलों को निपटा सकेंगे। इससे फाइलें लंबित नहीं होंगी और कामकाज में तेजी आएगी। इसके साथ ही प्रदेश के किसी भी होटल इकाई का स्टेटस कंप्यूटर पर एक क्लिक पर अपडेट हो सकेगा. उल्लेखनीय है कि एचपीटीडीसी के पूरे प्रदेश में करीब 16 कांप्लेक्स इंचार्ज हैं।

ऊना पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ

डीसी जतिन लाल ने बताया कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध संयुक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन में जिला ऊना को देशभर में प्रथम रहने पर पुरस्कृत किया गया।

उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार प्राप्ति में जिला के विभिन्न विभागों का व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ है। नशे के विरुद्ध नशामुक्त ऊना अभियान को धरातल पर कार्यान्वित करने में विभिन्न विभागों ने सराहनीय योगदान दिया है...

• सुनैना जसवाल/ऊना

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के एक युद्ध नशे के विरुद्ध संयुक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन में जिला ऊना पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। जिला ऊना को इस उपलब्धि पर 30 जून को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कृत किया गया। इस पुरस्कार को उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से प्राप्त किया है।

डीसी जतिन लाल ने बताया कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध संयुक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन में जिला ऊना को देशभर में प्रथम रहने पर पुरस्कृत किया गया। उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार प्राप्ति में जिला के विभिन्न विभागों का व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ है। नशे के विरुद्ध नशामुक्त ऊना अभियान को धरातल पर कार्यान्वित करने में विभिन्न विभागों ने सराहनीय योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि नशामुक्त ऊना अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला में कार्यान्वित किया गया। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।

उन्होंने कहा कि नशामुक्त ऊना अभियान के अंतर्गत नशे के विरुद्ध बच्चों और युवाओं को जागरूक बनाने के लिए जहां स्कूल और कॉलेज स्तर पर कौशल एवं जीवन विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जहां 26 हजार विद्यार्थियों को जोड़ा गया, तो वहीं लगभग 247 अध्यापकों एवं स्कूल प्रमुखों को भी प्रशिक्षित किया गया।

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जहां विद्यार्थियों के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना था, तो वहीं नकारात्मक विचारों से दूर रखना रहा, ताकि वे नशे से दूर रहें। इसके साथ-साथ हर घर दस्तक अभियान भी संचालित किया गया, जिसके माध्यम से एक लाख घरों तक नशे के विरुद्ध अलख जगाई और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया।

इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया। उपायुक्त ने नशामुक्त ऊना अभियान से जुड़ने के लिए जहां जिलावासियों का भी आभार जताया। वहीं, उम्मीद जताई कि भविष्य में भी जिला प्रशासन के इस तरह के अभियानों से जुड़कर जिला को नशामुक्त बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे।

अपना विद्यालय कार्यक्रम योजना

शिमला : हिमाचल प्रदेश में सभी सांसद, मंत्री, विधायक और अफसर सरकारी स्कूल गोद लेंगे। तीन विधानसभा उपचुनाव निपटने के बाद प्रदेश में अपना विद्यालय कार्यक्रम योजना लागू होगी। सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य से हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम तैयार किया गया है। गोद लेने वाले प्रतिपालक (मैंटर) बनकर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने और गुणात्मक शिक्षा के लिए भी सहयोग करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश से चुने गए लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद, सभी मंत्री, विधायक, श्रेणी-1 व 2 के राजपत्रित अधिकारी, जैसे उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपमंडलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी व पुलिस उपाधीक्षकों को कम से कम एक स्कूल गोद लेकर उसका संरक्षक बनना होगा। ये संरक्षक अध्यापकों और स्कूल प्रबंधन समितियों को स्कूलों में वांछित सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करेंगे। सचिवालय व निदेशालय में सेवाएं दे रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी, उपनिदेशक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के समन्वयक, प्रधानाचार्य, राज्य शिक्षा परिषद अनुसंधान व प्रशिक्षण और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारी भी 1-1 स्कूल गोद लेंगे और इसके मैंटर होंगे। राजकीय पाठशालाओं के लिए शैक्षिक सहायता टीम और गैर शैक्षिक सहायता टीमों का भी गठन किया जाएगा। यह टीम बिना किसी वित्तीय या अन्य लाभ के सरकार का सहयोग करेगी। अपना विद्यालय कार्यक्रम के लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। यह पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध रहेगा, ताकि जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण घटक व्यवस्थित किशोर प्रबंधन एवं मूल्यवर्द्धन संवाद है, जिसके तहत विभिन्न विभाग मिलकर स्कूली विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास व सशक्तिकरण करेंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि उपचुनाव समाप्त होने के बाद सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू इस योजना का शुभारंभ करेंगे।

• एचआरटीसी के लिए...

एडवाइजरी जारी

शिमला : बारिश के दौरान एचआरटीसी में सुरक्षित सफर को सुनिश्चित बनाने के लिए एचआरटीसी प्रबंधन ने एक एडवाइजरी अपने चालकों व परिचालकों के लिए जारी की है। इस पर सख्ती के साथ अमल करने को कहा है। एचआरटीसी के महाप्रबंधक पंकज सिंघल की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि बारिश व भूस्खलन के कारण सड़कें लगातार बंद हो रही हैं। धुंध के कारण बसों को चलाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। चालकों को निर्देश दिए हैं कि बरसात के दिनों में वाहन चलाते वक्त पूरी सावधानी बरतें। सड़क बंद होने की स्थिति में यदि बस फंस जाए, तो चालक-परिचालक यह सुनिश्चित करें कि बस को सुरक्षित स्थान पर खड़ी करें। यात्रियों एवं किसी अन्य व्यक्ति के दबाव में आकर वाहन चलाने का जोखिम न लें। बसों को क्रॉसिंग व पास देते समय सुरक्षित स्थान का चयन करें। रात के समय वर्षा के दौरान चालक सही लाइट का प्रयोग करें। बस को खड़ा करते समय हैंड ब्रेक गुटके या पत्थर का प्रयोग अवश्य करें।

• आलू के बीज की कीमत बढ़ी...

ऊना : प्रदेश के कृषि प्रधान जिला ऊना में इस सीजन आलू की खेती करना जमींदारों के लिए आसान नहीं होगी। फसल के बीज की कीमतों में तीन गुना वृद्धि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। अभी आलू की बुवाई के लिए दो माह का समय शेष है, लेकिन दूसरे राज्यों से व्यापारियों ने आलू का बीज 3000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा है। दूसरे राज्यों से जिला ऊना में किसानों को द्यबुवाई के समय 4000 रुपए प्रति क्विंटल के करीब पहुंच जाएगा।